

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड

27 नवंबर, 1970

[जे. सी. शाह, जी. के. मित्त, के. एस. हेगड़े, ए. एन. गोवर

और ए. एन. राय, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 286(2) जैसा कि वह मूल रूप से था — अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, का अर्थ।

करदाता, जिसका पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे में और उसका कारखाना बिहार में था, अपने नियुक्त विक्रेताओं और अन्य लोगों को ट्रकों, बस चेसिस और अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय कर रहा था। करदाता और नियुक्त विक्रेताओं के बीच समझौते किए गए थे, जिसके तहत प्रत्येक विक्रेता को एक क्षेत्र सौंपा गया था जिसमें केवल वह विक्रेता बिक्री कर सकता था। विक्रेताओं को मांगपत्र भेजने होते थे, खरीदे जाने वाले माल की कीमत चुकानी होती थी और बॉम्बे कार्यालय से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त करने होते थे। सुपुर्दगी आदेशों के अनुसरण में, ट्रकों आदि को बिहार में सुपुर्द किया गया था ताकि उन्हें वहां बिक्री के लिए उनके लिए सौंपे गए क्षेत्रों में ले जाया जा सके। यदि विक्रेता माल को बिहार राज्य के बाहर ले जाने की शर्त का पालन करने में विफल रहते, तो उन्होंने अपने अनुबंधों का उल्लंघन किया होता।

इस प्रश्न पर कि क्या 7 सितंबर 1955 से 31 मार्च 1956 की अवधि के दौरान, आवेदक द्वारा अपने विक्रेताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में बिक्री के लिए बिहार राज्य के बाहर की गई बिक्री से संबंधित कुल बिक्री, बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त थी, इस आधार पर कि बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी, अनुच्छेद 286(2) के तहत जैसा कि वह तब था।

अधिनिर्णित : जहाँ बिक्री के अनुबंध की शर्तों के तहत, खरीदार के लिए यह आवश्यक है, अनुबंध की एक आवश्यक घटना के रूप में, उस राज्य से माल हटाना जिसमें उसने माल खरीदा था और दूसरे राज्य में ले जाना, और जब माल को इस प्रकार हटाया जाता है, तो बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री माना जाना चाहिए। [854 जी- एच; 858 ए- बी]

त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाम द बॉम्बे कंपनी लिमिटेड [1952] एस.सी.आर. 1112, *त्रावणकोर कोचीन राज्य बनाम शनमुघा विलास काजू फैक्ट्री*, [1954] एस.सी.आर. 53, *बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य*, [1955] 2 एस.सी.आर. 603, *इंदुपुरी नरसिम्हम एंड संस बनाम उड़ीसा राज्य*, [1962] 1 एस.सी.आर. 314, *टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम एस. आर. सरकार*, [1961] 1 एस.सी.आर. 379, *द सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम मैसूर राज्य*, 14 एस.टी.सी. 175, *बेन गोर्म नीलगिरी प्लांटेशन्स कंपनी बनाम बिक्री कर अधिकारी, विशेष मंडल, एर्नाकुलम*, [1964] 7 एस.सी.आर. 706, *के. जी. खोसला एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम उप वाणिज्यिक कर आयुक्त, मद्रास*, 17 एस.टी.सी. 473 और *टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त एवं अन्य* [1970] 1 एस.सी.सी. 622, लागू।

काँफी बोर्ड, बेंगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास, 25 एस.टी.सी. 528, स्पष्ट किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1966 की दीवानी अपील संख्या 2402।

1962 के विविध न्यायिक वाद संख्या 284 में पटना उच्च न्यायालय के 4 मई, 1966 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

ए. के. सेन और यू. पी. सिंह, अपीलकर्ताओं के लिए।

एन. ए. पालकीवाला, एस. बी. मेहता, बी. दत्ता, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया।

हेगड़े, न्यायमूर्ति। यह विशेष अनुमति द्वारा की गई एक अपील है। यह बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 25 (3) के तहत एक संदर्भ में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई है। वह संदर्भ उच्च न्यायालय द्वारा करदाता कंपनी (यहाँ उत्तरदाता) के अनुरोध पर मांगा गया था। राजस्व बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित प्रश्न थे:

- " (1) उन बिक्रियों के संबंध में जो 1 अप्रैल, 1955 से 6 सितंबर, 1955 की अवधि में हुईं, क्या करदाता इन श्रेणियों की करदाता के संबंध में राजस्व बोर्ड द्वारा पाए गए तथ्यों के आधार पर, बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत दायित्व से छूट का हकदार है, क्योंकि उस प्रासंगिक तिथि पर मौजूद संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (क) के प्रावधान को उस अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाए।
- (2) उन बिक्रियों के संबंध में जो 7 सितंबर, 1955 से 31 मार्च, 1956 की अवधि में हुईं, क्या करदाता इन श्रेणियों की करदाता के संबंध में राजस्व बोर्ड द्वारा पाए गए तथ्यों के आधार पर, बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत दायित्व से छूट का हकदार है, इस आधार पर कि बिक्री अनुच्छेद 286 (2) के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी जैसा कि वह प्रासंगिक अवधि में था।"

उच्च न्यायालय ने पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक और करदाता के विरुद्ध दिया। उसने दूसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और करदाता के पक्ष में दिया। करदाता ने अपील नहीं की है। यह अपील बिहार राज्य द्वारा पहले संदर्भित दो प्रश्नों में से दूसरे पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय की शुद्धता को चुनौती देते हुए लाई गई है।

करदाता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत निगमित है। यह पूरे भारत में अपने नियुक्त विक्रेताओं, राज्य परिवहन संगठनों और व्यक्तिगत खरीदारों को ट्रकों और बस चेसिस और उनके अतिरिक्त पुर्जों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है। करदाता का पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे में है लेकिन उसका कारखाना जहाँ निर्माण प्रक्रिया की जा रही है, वह बिहार के जमशेदपुर में है। करदाता ने अपने ट्रकों, बस-चेसिस और अतिरिक्त पुर्जों की बिक्री के लिए पूरे भारत में कई विक्रेताओं को नियुक्त किया है। वे विक्रेता करदाता और उनके बीच संपन्न समझौतों के तहत नियुक्त किए गए हैं। विवादित टर्नओवर करदाता द्वारा अपने विक्रेताओं को डीलरशिप समझौतों के तहत उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में बेचे जाने वाले ट्रकों, बस-चेसिस और अतिरिक्त पुर्जों की बिक्री से संबंधित है। करदाता और उसके विक्रेताओं के बीच समझौते समान प्रतीत होते हैं। समझौतों के तहत, प्रत्येक विक्रेता को एक क्षेत्र सौंपा गया है जिसमें अकेले वह करदाता कंपनी से खरीदे गए ट्रकों, बस-चेसिस और अन्य अतिरिक्त पुर्जों को बेच सकता है। उसे अपने क्षेत्र के बाहर किसी भी खरीदार को उन वस्तुओं में से किसी को भी बेचने की मनाही है। समझौतों के अनुसार, विक्रेताओं को अपने मांगपत्र देने होंगे, खरीदे जाने वाले माल की कीमत चुकानी होगी और करदाता के बॉम्बे कार्यालय से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त करने होंगे। उन सुपुर्दगी आदेशों के अनुसरण में, ट्रकों, बस चेसिस और अन्य अतिरिक्त पुर्जों को बिहार में सुपुर्द किया गया था ताकि उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में ले जाया जा सके। बिक्री के अनुबंधों के तहत, विक्रेताओं को बिहार राज्य में उन्हें सुपुर्द किए गए ट्रकों, बस चेसिस और अतिरिक्त पुर्जों को बिहार के बाहर ले जाने की आवश्यकता थी। ये राजस्व बोर्ड द्वारा पाए गए तथ्य हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर, हमें यह तय करना है कि इस अपील में जिस बिक्री से हमारा संबंध है, क्या वह बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान हुई बिक्री है जैसा कि उस समय संविधान के अनुच्छेद 286 (2) द्वारा परिकल्पित था। दूसरे शब्दों में, निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या

वाणिज्य के उद्देश्य से की गई बिक्री थी या क्या वे अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री थी। जैसा कि पहले देखा गया है, उच्च न्यायालय ने यह माना है कि वे बिक्री अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई थी।

अनुच्छेद 286 (1) (ख) में दिखाई देने वाले वाक्यांश "के दौरान" पर *त्रावणकोर कोचीन राज्य और अन्य बनाम द बॉम्बे कंपनी लिमिटेड*¹ में विचार किया गया था। इसमें इस न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (ख) के अंतर्गत और कुछ आता हो या न आता हो, वे बिक्री और खरीद जो स्वयं माल के निर्यात या आयात का कारण बनती हैं, जैसा भी मामला हो, भारत के क्षेत्र से बाहर या उसमें, छूट के अंतर्गत आती हैं। उस मामले में इस न्यायालय ने आगे अवलोकन किया कि निर्यात द्वारा बिक्री में एकीकृत गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जो एक विदेशी खरीदार के साथ बिक्री के समझौते से शुरू होती है और भूमि या समुद्र द्वारा देश से बाहर परिवहन के लिए एक सामान्य वाहक को माल की सुपुर्दगी के साथ समाप्त होती है। ऐसी बिक्री को निर्यात से अलग नहीं किया जा सकता है जिसके बिना इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता है और बिक्री तथा परिणामी निर्यात एक ही लेनदेन के हिस्से बनते हैं। इन दो एकीकृत गतिविधियों में से जो मिलकर एक निर्यात बिक्री का गठन करती हैं, जो भी पहले घटित होती है उसे दूसरे के दौरान होने वाला माना जा सकता है। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां माल में संपत्ति विदेशी खरीदारों को हस्तांतरित हो गई थी और बिक्री इस प्रकार राज्य के भीतर माल की यात्रा शुरू होने से पहले पूरी हो गई थी, बिक्री को निर्यात के दौरान माना जाना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 286 (1) (ख) के तहत छूट दी जानी चाहिए। कानून का यही विवरण अनुच्छेद 286 के खंड (2) पर भी लागू होता है जैसा कि 11 सितंबर, 1956 को इसके संशोधन से पहले था।

अगला निर्णय जिसमें अनुच्छेद 286 (1) (क), 1 (ख) और (2) पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया, वह *त्रावणकोर कोचीन राज्य और अन्य बनाम शनमुघा विलास काजू*

¹ [1952] एस.सी.आर. 1112.

फैक्ट्री और अन्य² है। इसमें इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि "दौरान" (कोर्स) शब्द व्युत्पत्ति के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति को दर्शाता है और अनुच्छेद 286 (1) (ख) में "के दौरान" वाक्यांश न केवल उस समय की अवधि का संकेत देता है जिसके दौरान गति प्रगति पर है, बल्कि एक जुड़े हुए संबंध को भी दर्शाता है। नतीजतन, देश से बाहर निर्यात के दौरान एक बिक्री को अनुच्छेद 286 (1) (ख) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसका अर्थ न केवल देश से बाहर माल के निर्यात की दिशा में गतिविधियों के दौरान होने वाली बिक्री है, बल्कि ऐसी गतिविधियों के हिस्से के रूप में या उनसे जुड़ी हुई बिक्री भी है। लेकिन निर्यात के उद्देश्य के लिए माल की खरीद केवल उनके निर्यात की तैयारी का एक कार्य है न कि माल के निर्यात के दौरान किया गया कार्य।

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य³ में वेंकटराम अय्यर, न्यायमूर्ति ने अवलोकन किया कि बिक्री केवल तभी अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री हो सकती है जब दो शर्तें एक साथ हों (1) माल की बिक्री और (2) बिक्री के अनुबंध के तहत उन सामानों का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन।

इंदुपूरी नरसिम्हम एंड संस बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य⁴ में, इस न्यायालय ने माना कि बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय होने के लिए, यह आवश्यक है कि बिक्री या खरीद के अनुबंध के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का परिवहन होना चाहिए। राज्य के बाहर बिक्री के लिए राज्य के अंदर की गई खरीद को स्वयं अंतर-राज्यीय के दौरान नहीं माना जा सकता है और उस पर कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 286 (2) के प्रतिकूल नहीं है।

2 [1954] एस.सी.आर. 53.

3 [1955] 2 एस.सी.आर. 603.

4 [1962] आई, एस.सी.आर. 314.

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम एस. आर. सरकार और अन्य⁵ में इस न्यायालय ने माना कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 के खंड (ख) के भीतर वे बिक्री शामिल हैं जिनमें माल का स्वामित्व एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की गति के दौरान उनके स्वत्वाधिकार दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा पारित होता है और उन बिक्री को भी शामिल करता है जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की गति बिक्री के अनुबंध की एक शर्त या घटना का परिणाम होती है और माल का स्वामित्व किसी भी राज्य में पारित होता है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 का खंड (ख) कहता है:

"कि किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने को अधिकृत नहीं करेगा जहां ऐसी बिक्री या खरीद भारत के क्षेत्र में माल के आयात, या भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान होती है।"

द सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड और एक अन्य बनाम मैसूर राज्य और एक अन्य⁶, इस न्यायालय ने माना कि जहां बिक्री के अनुबंध की आवश्यकता के अनुसार माल को राज्य के बाहर ले जाया गया था, वे अंतर-राज्यीय बिक्री हैं और इसलिए बिक्री-कर से मुक्त हैं। उस मामले के तथ्यों पर यह माना गया कि बिक्री लेनदेन में स्वयं सीमा पार माल की आवाजाही शामिल थी।

बेन गोर्म नीलगिरी प्लांटेशन्स कंपनी कुन्नूर और अन्य बनाम बिक्री कर अधिकारी, विशेष मंडल, एर्नाकुलम और अन्य⁷ में इस न्यायालय को यह विचार करना था कि कौन सी बिक्री निर्यात के दौरान की बिक्री है और कौन सी बिक्री निर्यात के उद्देश्य के लिए है। निर्णय के दौरान शाह, न्यायमूर्ति (हम में से एक) ने अवलोकन किया:

5 [1961] आई एस.सी.आर. 379.

6 14, एस.टी.सी. 175. (एस.सी.)

7 17 एस.टी.सी. 473. (एस.सी.)

"निर्यात के दौरान एक बिक्री बिक्री और निर्यात के बीच एक संबंध को दर्शाती है, दो गतिविधियां इतनी एकीकृत होती हैं कि अनुबंध के उल्लंघन या लेनदेन की प्रकृति से उत्पन्न होने वाली मजबूरी के बिना दोनों के बीच संबंध को स्वेच्छा से बाधित नहीं किया जा सकता है। इस अर्थ में निर्यात के दौरान बिक्री का गठन करने के लिए यह कहा जा सकता है कि खरीदार और विक्रेता दोनों की ओर से निर्यात करने का इरादा होना चाहिए, निर्यात करने का दायित्व होना चाहिए, और एक वास्तविक निर्यात होना चाहिए। दायित्व कानून, पक्षों के बीच अनुबंध, या उनके बीच आपसी समझ या समझौते के कारण, या यहां तक कि लेनदेन की प्रकृति से उत्पन्न हो सकता है जो बिक्री को निर्यात से जोड़ता है। बिक्री का एक लेनदेन जो बेची गई वस्तु के निर्यात के लिए प्रारंभिक है, उसे निर्यात के लिए बिक्री माना जा सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से इसे निर्यात के दौरान नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि बिक्री निर्यात का कारण न बने।"

के. जी. खोसला एंड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम उप वाणिज्यिक कर आयुक्त, मद्रास⁸ में, इस न्यायालय ने माना कि इससे पहले कि एक बिक्री को आयात का कारण कहा जा सके, माल की गति अनुबंध के लिए आकस्मिक या अनुबंध की शर्तों के अनुसरण में होनी चाहिए और करदाता द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए माल को मोड़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कानून या अनुबंध के अनुसार मोड़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए न कि उनके उल्लंघन में।

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य⁹ में, इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद अवलोकन किया:

"यह तय किया गया है कि निर्यात के दौरान बिक्री, बिक्री और निर्यात के बीच संबंध दर्शाती है, दोनों गतिविधियां इतनी एकीकृत होती हैं कि अनुबंध के उल्लंघन या लेनदेन की प्रकृति से उत्पन्न मजबूरी के बिना दोनों के बीच के संबंध को स्वेच्छा से बाधित नहीं किया जा सकता है। निर्यात का अवसर देने के लिए बिक्री के अनुबंध और वास्तविक निर्यात के बीच ऐसा बंधन होना चाहिए कि प्रत्येक कड़ी अपने ठीक पहले वाली कड़ी से अटूट रूप से जुड़ी हो। सिद्धांत इस प्रकार निस्संदेह है, इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, कि अधिनियम (केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956) के तहत कर के योग्य होने के लिए बिक्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या वस्तुओं की आवाजाही का कारण दिखाया जाना चाहिए। आवाजाही बिक्री के अनुबंध की एक शर्त या घटना का परिणाम होनी चाहिए।"

यदि हम ऊपर संदर्भित निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि इस मामले में जिस बिक्री से हमारा संबंध है, वह अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान की गई बिक्री है। विक्रेताओं को उनके द्वारा खरीदे गए ट्रकों, बसों, चेसिस और अन्य अतिरिक्त पुर्जों को बिहार राज्य से बिहार के बाहर के स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता थी। वे करदाता के साथ उनके द्वारा किए गए अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ऐसा करने के लिए बाध्य थे। यदि वे माल को बिहार राज्य के बाहर ले जाने की आवश्यकता वाली शर्त का पालन करने में विफल रहते, तो उन्होंने अपने अनुबंधों का उल्लंघन किया होता और अपने डीलरशिप समझौतों में करदाता दंड के पात्र होते।

9 [1970] 1, एस.सी.सी 622.

तय किए गए मामले स्थापित करते हैं कि बिक्री को निर्यात या आयात के दौरान बिक्री या अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री निम्नलिखित परिस्थितियों में माना जाएगा:

- (1) जब निर्यात या आयात की धारा में मौजूद माल बेचा जाता है;
- (2) जब बिक्री के अनुबंध या कानून के तहत जिसके तहत माल बेचा जाता है, उन सामानों को किसी विदेशी देश में निर्यात करने या विदेशी देश से आयात करने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो, या उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में ले जाने की आवश्यकता होती है जिसमें माल की सुपुर्दगी होती है और
- (3) जहाँ बिक्री के अनुबंध की एक आवश्यक घटना के रूप में बेचे गए माल को उस राज्य से बाहर निर्यात या आयात या परिवहन करने की आवश्यकता होती है जिसमें माल की सुपुर्दगी होती है।

लेकिन श्री ए. के. सेन, बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'इस न्यायालय ने *काँफी बोर्ड, बँगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास और अन्य*¹⁰ में कानून का एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उनके अनुसार उस निर्णय का आधार यह है कि जब भी बिक्री के अनुबंध के अनुसरण में किसी राज्य में माल की सुपुर्दगी की जाती है, तो विचाराधीन बिक्री उस राज्य में कर योग्य हो जाती है जिसमें माल सुपुर्द किया जाता है जब तक कि उन्हें उपभोग के लिए राज्य से बाहर नहीं ले जाया जाता है न कि पुनर्विक्रय के लिए, या उन्हें उस राज्य में पुनर्विक्रय करने के लिए पहले से मौजूद समझौते के अनुसरण में राज्य से बाहर नहीं ले जाया जाता है जहां इसे ले जाया जाता है। *काँफी बोर्ड के मामले* (उपरोक्त) में निर्णय, हमारी राय में, इन तर्कों के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करता है।

10 25 एस.टी.सी. 528 (एस.सी.)

हमने पहले देखा है कि इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि जहां बिक्री के अनुबंध की शर्तों के तहत, खरीदार को उन सामानों को उस राज्य से हटाना आवश्यक है जिसमें उसने माल खरीदा था, दूसरे राज्य में ले जाना है और जब माल को इस तरह स्थानांतरित किया जाता है, तो विचाराधीन बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री माना जाना चाहिए। यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है। *कॉफी बोर्ड* मामले में इस न्यायालय ने इस स्थिति से कोई अलग रुख नहीं अपनाया, और न ही वह ऐसा कर सकता था क्योंकि पहले के फैसले उस पर बाध्यकारी थे। इसके अलावा अपने निर्णय के दौरान, विद्वान मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने न्यायालय के लिए बात की थी, ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का अनुमोदन के साथ उल्लेख किया जहां अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री और अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य के लिए बिक्री के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था। उस मामले के तथ्यों के आधार पर, महामहिम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विचाराधीन कॉफी का निर्यात उन बिक्री के साथ एकीकृत नहीं था जिनसे न्यायालय का संबंध था और निर्यात और बिक्री के बीच कोई सीधा बंधन नहीं था। अपने निर्णय के दौरान महामहिम ने अवलोकन किया:

"यहाँ निर्यात कार्यक्रम में दो स्वतंत्र बिक्री शामिल हैं। पहली बिक्री कॉफी बोर्ड के बीच विक्रेता के रूप में निर्यात प्रवर्तक को है। फिर निर्यात प्रवर्तक द्वारा एक विदेशी खरीदार को बिक्री होती है। बाद वाली बिक्री के बारे में, पहली बिक्री होने पर कॉफी बोर्ड को कोई भनक नहीं होती है। कॉफी बोर्ड की बिक्री किसी भी तरह से दूसरी बिक्री से संबंधित नहीं है। इसलिए, पहली बिक्री का दूसरी बिक्री से कोई संबंध नहीं है जो निर्यात के दौरान है, यानी, एक निर्यातक और एक आयातक के बीच माल की आवाजाही।"

यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से *कॉफी बोर्ड* के मामले (उपरोक्त) के तथ्यों और उन मामलों के तथ्यों के बीच अंतर को सामने लाता है जिनमें इस न्यायालय ने माना था कि विचाराधीन

बिक्री निर्यात या आयात के दौरान की गई बिक्री थी। कॉफी बोर्ड के मामले में इस न्यायालय ने पाया कि कॉफी बोर्ड द्वारा जिस बात पर जोर दिया गया था वह यह था कि निर्यात के उद्देश्य के लिए करदाता कॉफी का निर्यात किया जाना चाहिए; नीलामी में खरीदारों के लिए उस कॉफी का स्वयं निर्यात करना अनिवार्य नहीं था; वे इसे स्वयं कर सकते थे या वे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच सकते थे जो इसे भारत के बाहर निर्यात कर सकता था। उस आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कॉफी बोर्ड द्वारा की गई बिक्री निर्यात के दौरान की बिक्री नहीं है; वे केवल निर्यात के उद्देश्य के लिए बिक्री हैं। उस निर्णय का आधार हमारे सामने मौजूद तथ्यों पर लागू नहीं होता है। यहाँ, बिक्री के अनुबंधों की शर्तों के तहत, खरीदारों को बिहार राज्य से अन्य राज्यों में माल ले जाने की आवश्यकता थी। इसलिए इस मामले में जिस बिक्री से हमारा संबंध है, उसे अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की बिक्री माना जाना चाहिए।

ऊपर बताए गए कारणों से, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हैं। परिणामस्वरूप यह अपील विफल होती है और इसे लागत के साथ खारिज किया जाता है।

वी.पी.एस.

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।